*भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर : कुछ विचार**

श्री शक्तिकान्त दास

मुझे एफआईबीएसी वार्षिक सम्मेलन में पुन: आकर खुशी हो रही है। यह सम्मेलन विशेष है क्योंकि यह उद्योग जगत के नेताओं, वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों और विनियामकों को वर्तमान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता है। मैं इस वार्षिक सम्मेलन के आयोजन के लिए फिक्की और आईबीए को बधाई देता हूँ।

भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और बाजारों में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं और देश महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमारा देश कई कारकों के अनूठे मिश्रण से ताकत हासिल कर रहा है। इसकी आबादी युवा और गतिशील है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और विविधतापूर्ण है, लोकतंत्र मजबूत है और इसके पास उद्यमिता और नवाचार की समृद्ध परंपरा है।

इस पृष्ठभूमि में मैंने "भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर: कुछ विचार" विषय को चुना है। मैं चार मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले, मैं भारत की विकास संभावनाओं और उस दृष्टिकोण पर बात करूँगा जिसका हमें आगे बढ़ने के लिए पालन करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तीसरा, मैं हमारे वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा और अंत में मैं वित्तीय क्षेत्र से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें बताना चाहूंगा।

I. विकास की संभावनाएँ

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के कारण हुए संकुचन के बाद मजबूती से वापसी की है और पिछले तीन वर्षों के दौरान संवृद्धि 8.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक औसत दर से बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए, रिज़र्व बैंक ने 7.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने भी निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं का हवाला देते हुए भारत की जीडीपी वृद्धि को संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया है। दो दिन पहले, विश्व बैंक ने भी 2024-25 के लिए भारत के संवृद्धि पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत रखा है। पिछली तिमाही से संवृद्धि नरम रहने और पहली तिमाही में हमारे अनुमान से कम होने के बावजूद, आकंड़ों से पता चलता है कि बुनियादी विकास के चालक गति पकड़ रहे हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि **भारतीय विकास की गाथा बरकरार है**।

निजी खपत, जिसका कुल मांग में प्रमुख स्थान है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, में वृद्धि 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में 4 प्रतिशत की कमजोर वृद्धि थी। इससे ग्रामीण मांग के पूर्ववत होने की पुष्टि होती है। संवृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण चालक, अर्थात निवेश, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35 प्रतिशत है, अपनी हालिया गति को बनाए रखते हुए 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद का 90 प्रतिशत से अधिक अंश मजबूत गति से बढ़ा और वास्तव में 7 प्रतिशत से ऊपर रहा जबकि हेडलाइन आंकड़ा कम रहा। इसका कारण संभवत: केंद्र और राज्यों में लोकसभा चुनाव का होना हो सकता है जिसके कारण सरकारी व्यय में कमी रही। सरकारी उपभोग व्यय को छोड़ दें तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत रही।

आपूर्ति पक्ष देखें तो कृषि क्षेत्र में पहली तिमाही में मामूली अर्थात 2 प्रतिशत की वृद्धि रही लेकिन मानसून की अच्छी प्रगति, खरीफ की बेहतर बुवाई और रबी फसलों के लिए अच्छी नमी की स्थिति को देखते हुए आगे चलकर इसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। उद्योग और सेवाओं ने पहली तिमाही में क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो आर्थिक गतिविधि में निरंतर मजबूती दर्शाती है। निर्माण गतिविधि 10.5 प्रतिशत की दर से मजबूत रही।[1]

---

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से 5 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित वार्षिक एफआईबीएसी 2024 सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण।

[1] 2023-24 के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, 2024-25 की पहली तिमाही में निर्माण गतिविधि 10.5 प्रतिशत की तीव्र गति से बढ़ती रही।

आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों[2] के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण मजबूत रहा और इसमें 18.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। जुलाई 2024 में उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि जुलाई 2023 में वह 4.6 प्रतिशत थी। उद्योगक्षेत्र के भीतर, एमएसएमई ऋण में भी 14.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। रसायन और रासायनिक उत्पाद; खाद्य प्रसंस्करण; पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन; और बुनियादी ढाँचा जैसे उद्योगों को दिया गया बैंक ऋण जुलाई 2024 में काफी मजबूत रहा है। उद्योगक्षेत्र को बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह और अब तक का सबसे उच्च क्षमता उपयोग निवेश चक्र में वृद्धि की ओर इशारा करता है, जैसा कि एनएसओ आंकड़ों से परिलक्षित होता है।

यह स्पष्ट है कि भारत निरंतर विकास पथ पर है। संवृद्धि के दो मुख्य चालक – खपत और निवेश मांग, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्यों का सरकारी व्यय वर्ष की शेष तिमाहियों में बजट अनुमानों के अनुरूप गति पकड़ने की संभावना है। बैंकों और कॉरपोरेट्स की मजबूत बैलेंस शीट ने निजी पूंजीगत व्यय को और अधिक समर्थन देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। 2024-25 की पहली तिमाही में कॉरपोरेट मुनाफे (निवल) में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[3] सरकारी पूंजीगत व्यय मजबूत बना हुआ है। कुल मिलाकर, 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का रिज़र्व बैंक का 7.2 प्रतिशत का अनुमान समुचित प्रतीत होता है।

मध्यम से दीर्घावधि में विकास की संभावनाओं के संबंध में ऐसा महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तनकारी बदलावों के मोड़ पर है। इस तथ्य से, कि वैश्विक विकास मामूली रहने और वैश्विक चुनौतियां बनी रहने के बावजूद विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह संकेत मिलता है कि संरचनात्मक चालक भारत के व्यापक आर्थिक परिणामों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन चालकों में शामिल हैं: मजबूत भौतिक अवसंरचना के निर्माण पर नीतिगत जोर; तेजी से बढ़ती हमारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकीय प्रगति; तथा प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार।

2047 तक उभरती अर्थव्यवस्था से उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलने की आकांक्षा को साकार करने के लिए, **भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी**। हमारा ध्यान आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों से विकास के सभी चालकों को नियोजित करने पर होना चाहिए। आपूर्ति पक्ष की प्राथमिकता में कृषि, उद्योग और सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि भारत में कृषि में अपार संभावनाएं हैं। बागवानी, खाद्य तेल, डेयरी, पोल्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण आदि में कृषि-वाणिज्यिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकती हैं। हमारा दृष्टिकोण उत्पादकता के साथ-साथ अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने का होना चाहिए ताकि हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्व निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें।

अधिक रोजगार पैदा करने में विनिर्माण क्षेत्र का संभाव्य योगदान महत्वपूर्ण होगा। 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)' और 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई)' योजना जैसी पहलें विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने और तेजी से बढ़ने में मदद कर रही हैं। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र संवृद्धि और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बहुत आशाजनक है। कुल मिलाकर, विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी होना चाहिए।

सेवा क्षेत्र, जो पिछले कई दशकों से विकास का मुख्य आधार बना हुआ है, को उच्च मूल्य-वर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवसरों के नए आयाम तलाशने चाहिए। इसके अलावा, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुसंधान और विकास पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना भी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास के लिए अधिक निधि आबंटन तथा सरकारी पहलों के साथ, निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदार हो सकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, खपत जैसे प्रमुख मांग चालकों, निवेश और वस्तुओं तथा सेवा निर्यात की गति एक जैसी होनी चाहिए। घरेलू खपत अधिक होने से अर्थव्यवस्था को बाहरी अनिश्चितताओं से बचाने में मदद होगी। अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विकास के लिए निवेश महत्वपूर्ण है और अनुकूल कारकों के वर्तमान संगम को देखते हुए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को बड़े पैमाने

---

[2] बैंक ऋण का क्षेत्रीय प्रयोग - जुलाई 2024 (आरबीआई द्वारा 30 अगस्त 2024 को जारी डेटा)।

[3] 2,934 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स के निवल मुनाफे में 2024-25 की पहली तिमाही में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही में यह 6.4 प्रतिशत थी। (2024-25 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉरपोरेट व्यवसाय क्षेत्र का प्रदर्शन, आरबीआई द्वारा 30 अगस्त, 2024 को जारी)।

पर आगे आने का समय है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ते हुए बाहरी मांग की क्षमता का हमारे लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था के व्यापक आधार वाले विकास को बढ़ावा देने और उसको गति देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के लिए **पिछले सुधारों के लाभों को संरक्षित करना और अधिक सुधारों के साथ भारत की सुधार यात्रा को गति देना भी आवश्यक होगा**। आर्थिक दृष्टिकोण से, ऐसे सुधार जिन्होंने बड़े परिवर्तन किए हैं और हमारी स्थिरता और विकास के प्रयासों को मजबूत किया है, उनमें शामिल हैं: (i) रुपये की प्रशासित विनिमय दर से बाजार निर्धारित व्यवस्था में परिवर्तन; (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा बजट घाटे के वित्तपोषण के स्वचालित मुद्रीकरण को रोकना; (iii) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएफ) अधिनियम बनाना; (iv) लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की शुरुआत; (v) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन; और (vi) माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन। इन छह सुधारों में से प्रत्येक ने दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इन सुधारों को भूमि, श्रम और कृषि बाजारों में सुधारों द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि हमने इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति की है, अभी भी राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कारोबार करने में सरलता बढ़ाने से, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

II. मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

2022 की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद खाद्य, कमोडिटी और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आने के कारण मुद्रास्फीतिक दबाव में तीव्र वृद्धि हुई। प्रतिकूल घरेलू मौसम के सतत आघातों ने इसे और तीव्र कर दिया। रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों, सरकार की ओर से आपूर्ति पक्ष के उपायों और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट के कारण 2023-24 की शुरुआत से मुद्रास्फीति में गिरावट आई। फिर भी, अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से अवस्फीति की गति अक्सर बाधित होती है। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति है जो मायने रखती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति का भार 46 प्रतिशत है जिसे लोग समझते हैं। मानसून के अच्छे रहने और खरीफ की अच्छी बुवाई से बेहतर फसल की संभावनाएँ बढ़ने से इस बात की अधिक आशा है कि वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक अनुकूल हो।

हमें इस बात पर नज़र रखनी होगी कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली ताकतें कैसे काम करती हैं। मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है। हमें अवस्फीति के अंतिम पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना होगा, तथा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा जो एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। मौद्रिक नीति द्वारा टिकाऊ संवृद्धि के लिए किया जा सकने वाला सबसे अच्छा योगदान मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है।

III. वित्तीय क्षेत्र - भविष्य के लिए नींव को मजबूत करना

भारत के वित्तीय क्षेत्र ने चुनौतियों और संकटों से पार पाने की अपनी क्षमता का समय-समय पर प्रदर्शन किया है। वित्तीय क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद उल्लेखनीय सुदृढ़ता दिखाई। आज वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख संकेतक इसके मजबूत स्वास्थ्य को दर्शाते हैं[4]। यह सुदृढ़ता, अन्य ताकतों के साथ मिलकर भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है।

इस परिवेश में, वित्तीय क्षेत्र को वित्तीय समावेशन अधिक गहरा करने, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुँच को व्यापक बनाने और समग्र समावेशी विकास का समर्थन करने की आवश्यकता है। उसे डिजिटल बैंकिंग में नवाचार को बढ़ावा देने, टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देने और एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है जो उभरती चुनौतियों का सामना कर सके और विकास के दिशापथ को बेहतर बनाने में मदद कर सके।

---

[4] बैंकों का जीएनपीए अनुपात जून 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के अंत के बाद से सबसे कम था। वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, जून 2024 के अंत में लगातार घटते हुए 1.3 प्रतिशत पर पहुंचा है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार जारी रहा और जून 2024 के अंत तक यह 76.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। पूंजी तथा जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जून 2024 के अंत में 16.8 प्रतिशत रहा, जो विनियामक सीमा से काफी ऊपर है। वार्षिक लाभप्रदता संकेतक, अर्थात् आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) जून 2024 के अंत में क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत रहे, जो निरंतर सुधार दर्शाते हैं।

चूंकि वित्तीय क्षेत्र अब एक मजबूत स्थिति में है, इसलिए इस स्थिरता को सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, खासकर बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में। वित्तीय संस्थानों को अपने व्यवसाय मॉडल का लगातार मूल्यांकन और परिशोधन करना चाहिए, उभरते जोखिमों को पहचानना और उनसे निपटना चाहिए और हर नए अवसर का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अब समावेशी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। हालांकि जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी जैसे आर्थिक विकास के पारंपरिक आंकड़े प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, किंतु वे अकेले किसी राष्ट्र के लिए वास्तव में विकसित होने के मतलब की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं।

भारत ने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति[5] की है। एक सच्चे विकसित भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक की, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो और उसके पास आवश्यक वित्तीय साक्षरता हो। वित्तीय क्षेत्र बैंकिंग, ऋण और बीमा तक पहुँच का विस्तार करके और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शक्ति का उपयोग करके हाशिए पर खड़े वर्गों तक पहुँचकर समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) कार्यक्रम वंचित वर्गों के संबंध में ऋण अंतराल को दूर करने में महत्वपूर्ण है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) की शुरुआत ने वित्तीय पहुँच को आगे बढ़ाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा पेश किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 के 53.9 से बढ़कर 64.2 हो गया है, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में की गई प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि, इन सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

दो और प्रमुख चालकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्व-संचालित और सहयोगी दोनों तरीकों को अपनाया है। हम मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं और साथ ही लक्षित वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। रिज़र्व बैंक ने अन्य वित्तीय विनियामकों के साथ सहयोग करते हुए वित्तीय साक्षरता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना में सहायता की है। बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, देश के लगभग सभी ब्लॉकों को शामिल करते हुए 2,421 वित्तीय साक्षरता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर रिज़र्व बैंक ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार के विकास को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और इनोवेशन हब जैसी अन्य पहलों ने हमारे फिनटेक इकोसिस्टम को समृद्ध करने के लिए एक मजबूत वातावरण को बढ़ावा दिया है। अबाधित ऋण के लिए रिज़र्व बैंक की पायलट परियोजना, अर्थात् एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत से ऋण तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है, विशेष रूप से किसानों और एमएसएमई के लिए।

IV. वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाएँ

वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन की सुरक्षा के बारे में बात करने के बाद, मैं अब कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जहाँ मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र भारत की विकास आकांक्षाओं में योगदान दे सकता है।

(ए) महिला श्रम भागीदारी में सुधार

भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी वैश्विक औसत से कम है। यह अंतर लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार और सामाजिक बाधाओं को दूर करने जैसी लक्षित पहलों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उद्यमिता आर्थिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर भी भारत में, एमएसएमई के पांचवें हिस्से से कम महिलाओं के स्वामित्व में है। महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी तक सीमित पहुँच, प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड और किफायती वित्त तक

[5] नीति आयोग द्वारा जारी भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी - एक चर्चा पत्र, प्रो. रमेश चंद और डॉ. योगेश सूरी, नीति आयोग, जनवरी 2024।

पहुँचने में कठिनाइयों सहित बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय क्षेत्र को सहायक नीतियों को लागू करके, अनुरूप वित्तीय उत्पाद बनाकर और वित्त तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाते हुए इस लैंगिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसे दो मोर्चों पर आगे बढ़ाया जा सकता है - पहला, वित्तीय संस्थानों में महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करके; और दूसरा, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं द्वारा चालित व्यवसायों के अनुरूप बैंकों की अपनी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों का समर्थन करके। बैंक सक्रिय रूप से बड़ी संख्या में महिला बीसी यानी 'बैंक साथी' या 'सखी' को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं, खासकर एसएचजी सदस्यों में से।

(बी) *एमएसएमई का समर्थन*

हमारी बड़ी युवा आबादी को देखते हुए हमें रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने की आवश्यकता है। उनके महत्व के बावजूद, कई एमएसएमई छोटे आकार के बने हुए हैं और विभिन्न चुनौतियों के कारण प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें किफायती वित्त तक पहुंच भी एक बाधा है।

वित्तीय क्षेत्र एमएसएमई का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने वाले अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं। इसमें सुविधाजनक ऋण विकल्प प्रदान करना, कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार करना और एमएसएमई के विशिष्ट नकदी प्रवाह चक्रों और विकास चरणों को समायोजित करने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। यह एमएसएमई को विकसित करने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा अनुकूल संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। हाल के वर्षों में अपनाए गए नीति उपायों ने अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित मूल तत्वों को मजबूत किया है और सुरक्षितता को बढ़ाया है। खपत, जो हमारे विकास का मुख्य चालक रहा है, ने ग्रामीण मांग में सुधार के साथ गति पकड़ी है। निवेशकों का विश्वास सर्वकालिक उच्च स्तर पर है; बैंक और कॉरपोरेट के तुलनपत्र मजबूत हैं; और संरचनात्मक सुधार हमारे विकास की सीमा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

हम एक गतिशील और अनिश्चित दुनिया में रह रहे हैं, और हमें सतर्क रहने और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। नए अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जब मैं हमारी युवा आबादी में उद्यमशीलता के उत्साह और प्रतिभा को देखता हूं, तो यह मुझे भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त करता है।

धन्यवाद। नमस्कार।